

## पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशेष सहायता योजना

### प्रलमिस के लयि:

पूँजीगत नविश हेतु राज्यों को वशेष सहायता, प्रधानमंत्री गत शकत भासटर प्लान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, ऑप्टकिल फाइबर केबल ।

### मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हसतकषेप, वृद्धि और वकिस, बुनयिादी ढाँचा ।

## चरचा में क्यँ?

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2022-23 के लयि पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशेष सहायता योजना शुरू की है ।

## पूँजी नविश हेतु राज्यों को वशेष सहायता योजना:

### परचिय:

- इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूँजी नविश परयोजनाओं के लयि 50 वर्षीय ब्याज़ मुक्त ऋण के रूप में वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
- वत्तीय वर्ष 2022-23 के लयि राज्यों को कुल 1 लाख करोड़ रुपए की वत्तीय सहायता दी जाएगी ।
- इस योजना के तहत दयिा जाने वाला ऋण वत्तीय वर्ष 2022-23 के लयि राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधार सीमा से अधिक होगा और इसे उसी वत्तीय वर्ष में खरच करना होगा ।

### योजना हेतु पात्र:

- नई परयोजनाओं या चल रही पूँजीगत परयोजनाओं में लंबति बलियों के नपिटान के लयि ।
- राज्य अपनी वरीयता/प्राथमकता दर्शाते हुए आवंटति नधि से अधिक मूल्य की परयोजनाएँ प्रसतुत कर सकते हैं ।

### योजना के वभिन्न भाग:

- पूँजीगत कार्यों के लयि [\(प्रधानमंत्री गत शकत भासटर प्लान को प्राथमकता मलिंगी\)](#); प्रधानमंत्री गत शकत से संबधति खरच; [प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना](#); डजिटिलीकरण के लयि प्रोत्साहन; [ऑप्टकिल फाइबर केबल](#); शहरी सुधार; वनिविश और मुद्रीकरण ।

- अयोग्यता:** 5 करोड़ रुपए से कम (पूर्वोत्तर के लयि 2 करोड़) के पूँजीगत परवियय वाली परयोजनाएँ और पूँजीगत परवियय के बावजूद मरममत एवं खरखाव परयोजनाएँ पात्र नहीं हैं ।

## पूँजीगत व्यय:

### अरथ:

- पूँजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुवधियों, शकिस आदि के वकिस पर सरकार द्वारा खरच कयिा गया धन है ।
- इसमें सरकार द्वारा भूमि और नविश जैसी अचल संपत्तयिँ के अधगिरहण पर होने वाला खरच भी शामिल है जो भवषिय में लाभ या लाभांश देता है ।
- संपत्तिकाे नरिमाण के साथ-साथ ऋण का पुनर्भुगतान भी पूँजीगत व्यय है, क्यँक यह देयता को कम करता है ।
- पूँजीगत व्यय नविश या वकिस संबंधी व्यय से जुड़ा होता है, जहाँ व्यय का लाभ भवषिय में वर्षों तक प्राप्त होता है ।

### महतत्व:

- पूँजीगत व्यय प्रकृति में दीर्घकालक है और उत्पादन हेतु सुवधियों के संयोजन या सुधार एवं परचालन दक्षता को बढ़ाकर अरथव्यवस्था को कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है ।
- इससे शर्म भागीदारी को बढ़ावा मलिन के साथ भवषिय में अरथव्यवस्था में अधिक उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ावा मलित है ।

### राजस्व व्यय से अंतर:

- पूँजीगत व्यय, जसिसे भवषिय के लयि संपत्तिकाे नरिमाण होता है, के वपिरीतराजस्व व्यय से न तो संपत्तिकाे नरिमाण होता और न ही इससे सरकार के कसिी दायतिव में कमी आती है ।

◦ कर्मचारियों का वेतन, पछिले करज पर ब्याज़ भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदिराजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। यह प्रकृतमें आवर्ती है।

### नमिनलखिति में से कौन भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल है/हैं? (2016)

1. सड़कों, भवनों, मशीनरी आदि जैसी संपत्तियों के अधगिरहण पर व्यय।
2. वदिशी सरकारों से प्राप्त ऋण
3. राज्यों और केंद्रशासति प्रदेश को दयि गए ऋण और अग्रमि

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- **पूंजीगत बजट:** इसे बजट के उस हसिसे के रूप में परभाषति कयि जा सकता है, जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय से संबंधति है।
- **पूंजीगत प्राप्तियाँ :** पूंजीगत प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों को संदर्भति करती हैं जो या तो एक दायतिव पैदा करती हैं या सरकार की संपत्ति में कमी का कारण बनती हैं। आमतौर पर सरकार की गैर-राजस्व प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में जाना जाता है। इनमें ऋण वसूली, सरकार द्वारा उधार (बाज़ार , वदिशों और बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण), सरकार की अन्य प्राप्तियाँ जैसे- ङाक जमा, भवषिय नधि आदि शामिल हैं। **अतः कथन 2 सही है।**
- **पूंजीगत व्यय:** ऐसा व्यय जो या तो संपत्ति सृजति करता है (उदाहरण के लयि सड़क, स्कूल का नरिमाण) या देयता को कम करता है (उदाहरण के लयि ऋण का भुगतान ) पूंजीगत व्यय कहलाता है। इनमें सरकार द्वारा ऋण वतिरण (राज्यों एवं केंद्रशासति प्रदेशों को दयि गए ऋण तथा अग्रमि) और ऋण भुगतान ; सड़कों, भवनों, मशीनरी आदि जैसी संपत्तियों के अधगिरहण पर व्यय एवं रक्षा, सामान्य सेवाओं व अन्य देनदारियों पर सरकार का पूंजीगत व्यय शामिल है। **अतः कथन 1 और 3 सही हैं।**

अतः वकिल्प (d) सही उत्तर है।

[सरोतः पी.आई.बी.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/scheme-special-assistance-to-states-for-capital-investment>